FEBRUARY 2023, INDORE

COT COSMOS

AN INNITIATIVE BY SMART INFO GROUP

“टेक्सटाइल सेक्टर के हाथ लगी निराशा फिर भी बजट को कहा “भविष्यवादी”

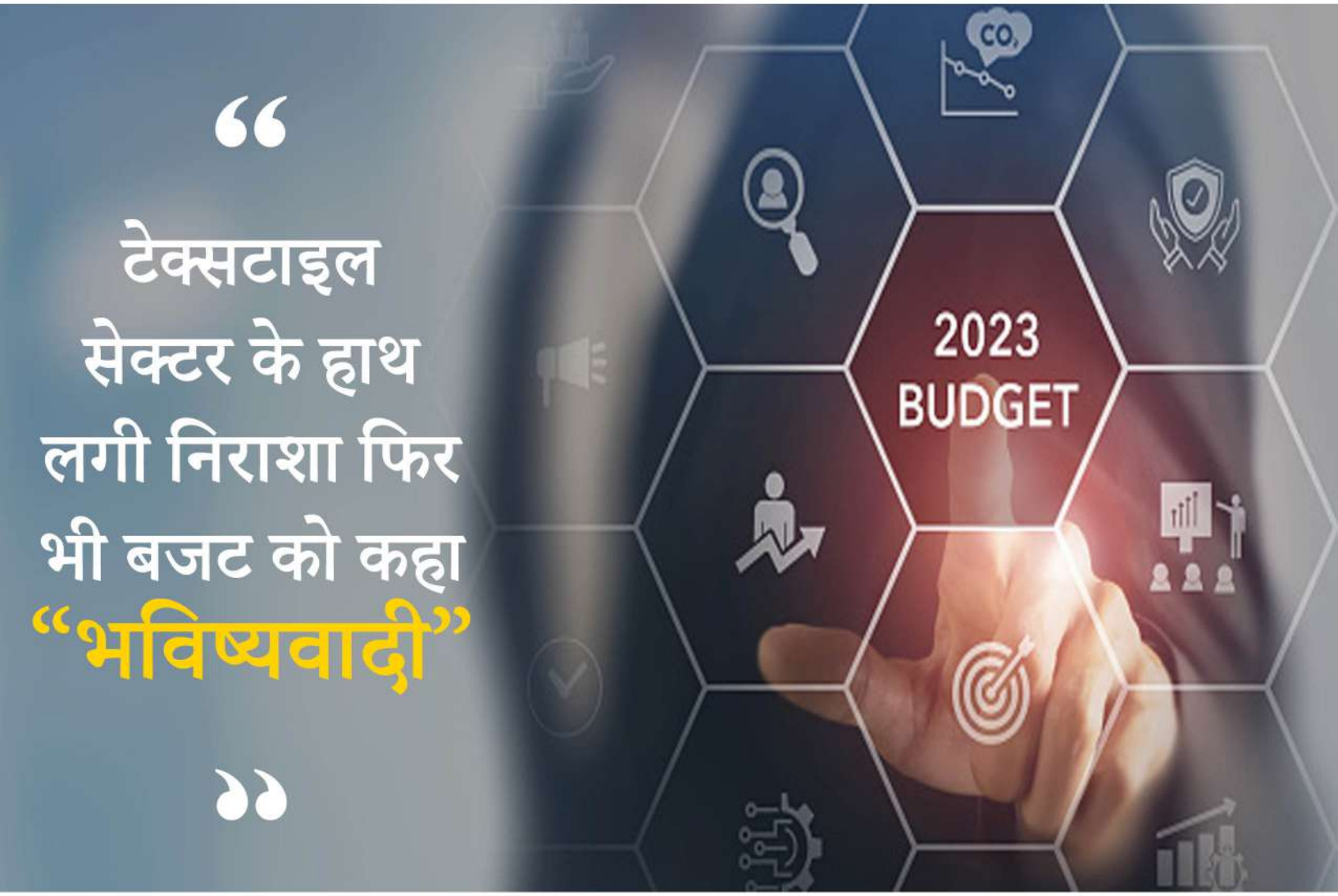

भारत के कपड़ा उद्योग ने देश के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का स्वागत किया है और इसे "व्यावहारिक और भविष्यवादी" करार दिया है। बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की उम्मीद तो पूरी नहीं हुई लेकिन माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में 2200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यह कोष ईएलएस कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवंटित किया गया है।

सीएआई प्रेसिडेंट अतुल गनात्राजी ने कहा कि भारत के लिए यह बहुत उपयोगी होगा क्योंकि वर्तमान में हमारी ईएलएस कपास की आवश्यकता लगभग 10 लाख गांठ है लेकिन इसके मुकाबले हम भारत में केवल 3.5 से 4 लाख गांठ ईएलएस कपास का उत्पादन कर रहे हैं, और शेष 6 लाख गांठ हम संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात कर रहे हैं ।

कहा जा रहा है कि यह राशि उन राज्य सरकारों को आवंटित की जाएंगी जहां यह ईएलएस कपास पहले से ही बढ़ रहा है यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्य। पीपीपी योजना के तहत अनुबंध खेती होगी और बीज सिटी और सिमा द्वारा दिया जाएगा, ऐसा करने से आने वाले वर्षों में ईएलएस कपास का उत्पादन बढ़ेगा और आयात बिल कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

आज की स्थिति में हमारे भारतीय ईएलएस कपास डीसीएच-32 की दर 70,000 पर कैंडी है और यूएसए ईएलएस कपास पीआईएमए की दर 1,50,000 पर कैंडी है, इसलिए यदि हमारे ईएलएस कपास का उत्पादन भारत में बढ़ेगा तो हमारा कपड़ा उद्योग बहुत पैसा बचाएगा और सभी को लाभ होगा।

"सिटी, सिमा जैसे हमारे संघ इस परियोजना में बहुत विशेषज्ञ हैं और उन्होंने पहले से ही इस तरह के काम के लिए कई मील के पत्थर हासिल किए हैं इसलिए जैसे ही यह योजना निधि हमें आवंटित की जाएगी, हम इस निधि का उपयोग करना शुरू कर देंगे और इस परियोजना पर काम शुरू कर देंगे। हम सभी एसोसिएशन CITI, SIMA, CCI और CAI मिलकर काम करेंगे और भारत में ELS कपास को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।"

अतुल गनात्रा,
CAI PRESIDENT

इन उम्मीदों पर फिरा पानी

- -बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कपास और पर से 11% आयात शुल्क हटाने की मांग
- सभी प्रकार की टेक्सटाइल मशीनरी पर 31 मार्च 2023 तक 5% आयात शुल्क बनाएं रखें।
- कपड़ा मूल्य श्रृंखला के लिए प्रोत्साहन योजना।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना।

वित मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा

"ईएलएस कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, हम सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित और मूल्य के माध्यम से एक क्लस्टर (पीपीपी) श्रंखला दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसका मतलब इनपूट आपूर्ति, विस्तार सेवाओं और बाजार के लिए किसानों, राज्य और उद्योग के बीच सहयोग होगा।"

घोषणा का असर

इस खबर के आते ही सूती कपड़ा शेयर मार्केट में सकारात्मक माहौल छा गया। एनएसई पर सुबह के सौदों में इन शेयरों में 3% तक की तेजी आई । एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, भारत में सूती विशेष धागे और सूती सिलाई धागे के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक, 3.19% बढ़कर 103.65 रुपये हो गया। इस बीच, अंबिका कॉटन मिल्स (0.13%), नितिन स्पिनर्स (2.72%), गिन्नी फिलामेंट्स (0.63%), और अरविंद (2.30%) ने घोषणा के बाद 3% की बढ़त हासिल की।

पंजाब-हरियाणा और राजस्थान को नहीं मिलेगा घोषणा का लाभ

पंजाब में किसानों और कपास उद्योग के लोगों का कहना है कि चूंकि अतिरिक्त लंबे स्टेपल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, इसलिए पंजाब के उत्पादक स्वतः ही इससे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आम तौर पर पंजाब और हरियाणा में 27.5-28.5 एमएम लंबे स्टेपल का कच्चा कपास पैदा होता है, लेकिन चालू सीजन में किसानों को 27 एमएम से भी कम लंबे स्टेपल मिले। इस घोषणा से दक्षिण,पश्चिम या मध्य भारत के कपास उत्पादकों को लाभ होगा।

समझें क्यों है भविष्यवादी

उद्योग जगत के दिग्गज इस बजट को भविष्यवादी कह रहे है। उनका मानना है कि यह बजट आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसे में जब आम आदमी के पास पैसे की बचत होगी तो गारमेंट सेक्टर में बिक्री की संभावना बढ़ेगी। नतीजा, खपत बढेगी और भविष्य में उद्योग को लाभ होगा।

हालात नहीं सुधरे तो खत्म हो जाएंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री

साल **2013** से ही स्पिनिंग इंडस्ट्री का बुरा दौर शुरू हो गया था। बीच में कोविड के दौरान मिल्स के हालात बेहतर हुए थे लेकिन**,** पिछले **2** साल से तो स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। **20** साल पहले हमारे सोलापुर शहर में लगभग **15** स्पिनिंग मिल्स हुआ करती थी। यहां का टर्किश टॉवल और बेडशीट्स विश्व में प्रसिद्ध थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहां केवल हमारी **1** स्पिनिंग मिल बची है। और वो भी मौजूदा हालात में लगभग बंद जैसी स्थिति में है।

महराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र की जानी मानी स्पिनिंग मिल स्वामी समर्थ के मालिक राजशेखर शिवधरे से खास बातचीत

कॉटन के बढ़े हुए दाम, कपास की कम आवक और उसकी तुलना में यार्न की मांग में लगातार कमी। ये तमाम कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोखला करते जा रहे है। यदि हालात नहीं सुधरे तो जल्द ही यह पूरी इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएंगी। एसआईएस से साक्षात्कार में यह चिंता जाहिर की महराष्ट्र के सोलापुर जिले के वलसंग गांव में पिछले 25 सालों से स्पिनिंग मिल चला रहे राजशेखर शिवधरे ने।

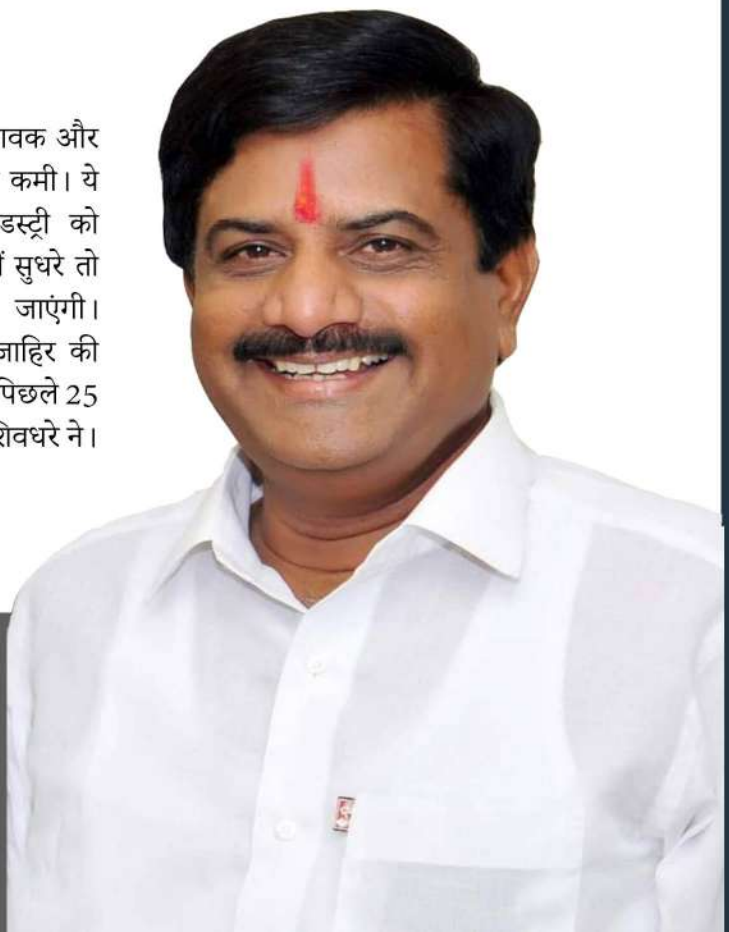

राजशेखर शिवधरे
(SPINNER)
वलसंग गांव, सोलापुर, महराष्ट्र

> “360 दिन 24 घंटे चलने वाली इंडस्ट्री पर ताला लगने की नौबत आ गई है। अकेले महराष्ट्र में ही लगभग 140 स्पिनिंग मिल्स रजिस्टर्ड है लेकिन मौजूदा वक्त में महज 60 मिल्स ही काम कर रही है और वह भी आधी से भी कम क्षमता में।”

उन्होंने बताया कि किसी भी फसल की बुवाई के आंकड़ों से पैदावार का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। कपास की आवक का पुर्वानुमान हर बार उसकी बुवाई के रकबे के आधार पर लगाना शुरू कर दिया जाता है जबकि फसल पूरी तरह प्राकृतिक माहौल पर निर्भर करती है। इस बार भी देर तक हुई बारिश ने कपास के सारे पूर्वानुमानों पर पानी फेर दिया और अब कुछ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

इस सीजन बारिश ने बहुत से राज्यों में कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है। महराष्ट्र उन्हीं में से एक है। महराष्ट्र के वेस्ट झोन में कपास की पैदावार 30 से 40 प्रतिशत तक कम हुई है। लेकिन पैदावार कम होने की वजह से मंडी में आवक धीमी नहीं हुई है बल्कि आवक धीमी इसलिए है क्योंकि किसानों को पिछले साल की तरह 12 हजार रूपए क्विंटल में अपना कपास बेचना है। इस कीमत पर जिनर्स कपास खरीद नहीं रहे और कम कीमत पर किसानों को कपास बेचना नहीं है।

वर्तमान समय जिनिंग फैक्ट्री और स्पिनिंग मिल्स दोनों के ही लिए चुनौतिभरा है। मिल्स तो कुछ महीनों पहले से ही 50 प्रतिशत या इससे कम क्षमता पर काम कर रही है अब जिनिंग फैक्ट्री के लिए भी यही संकट आ खड़ा है। ना तो कॉटन का सप्लाय रेग्यूलर है और ना ही कॉटन और यार्न के रेट का अंतर कम हुआ है। मेरा सवाल यह है कि जब रॉ कॉटन कम है तो सरकार उसका एक्सपोर्ट क्यों कर रही है। रॉ मटेरियल की जगह हमें फिनिश गुड का एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री की स्थिति में सुधार हो।

सुझाव

- सरकार को कॉटन का एक्सपोर्ट बंद करके यार्न और गारमेंट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए।
- इंडस्ट्री के लिए बिजली बिल में जो सब्सिडी दी जा रही है वह बहुत कम है, बिजली शुल्क को कम करना भी हमारे लिए एक बड़ी मदद होगी।
-वर्तमान में कोई भी बैंक स्पिनिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस नहीं दे रही है क्योंकि इंडस्ट्री लॉस में है। सरकार को इसके लिए भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए।

Sk.Amjat (Managing Director)
+91 88885 85788
+91 9404467088
skskamjat@gmail.com

GST No. 27DCHPS5982M1ZL

The Name Of Trust

Maharashtra INDUSTRIES

Ginning & Pressing Automation Systems

Hot Box,Automatic R.C. Feeding System (Trolley) One by One Lint Suction System, Super Cleaner,R.C. & Press Belt System, Seed Screw Conveyor Ginning Pressing All Solution.

Navsari Square, Walgaon Road, Amravati. 444601 (M.S.)

कॉटन के मौजूदा सीजन में मंडियों में कपास की धीमी आवक पूरे उद्योग के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जिनर्स के लिए काम करने का सीजन ही 6 से 8 महीने का होता है। उसमें भी स्थिति यह है कि फैक्ट्री चलाने के लिए माल ही नहीं है। नतीजा, ज्यादातर जिनिंग फैक्ट्री या तो अपनी आधी क्षमता पर काम कर रही है या बंद है। यह कहा जाए कि उद्योग की कमान किसान के हाथ में है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि, जब किसान अपना माल बेचने को तैयार होगा तभी व्यापार को गति मिल पाएंगी। वर्तमान परिदृश्य में तो किसान गेम चेंजर की भूमिका निभा रहे हैं। यह बात कहीं नागपुर के समीप स्थित तलेगांव क्षेत्र के जाने-माने जिनर गिरीश राठी ने।

गेम चेंजर की भूमिका में है कपास किसान

गिरीशजी ने बताया कि कॉटन इंडस्ट्री में हमने साल 2004 से शुरूआत की। वर्तमान में हमारी 4 जिनिंग फैक्ट्री है जिसे मैं और मेरे अनुज राधे राठी मिलकर संभालते है। इसके अलावा सीड और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम पिछले 35 साल से काम कर रहे है। इस वजह से किसानों से सीधे जुड़े हुए है और उनकी समस्याओं को समझ पाते है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार को अपने प्रयास तेज गति से करने होंगे। अच्छी बात यह है कि आज के युवा किसान नई टेक्नोलॉजी को समझने और अपनाने के लिए एकदम तैयार है।

सुधर रही है स्थिति

उन्होंने बताया कि इस बार विदर्भ में कपास की पैदावार भी 10 से 20 प्रतिशत तक कम हुई है। अत्यधिक बारिश की वजह से फसल को खासा नुकसान हुआ है। धीमी आवक की एक वजह पैदावार कम होना भी है। हालांकि अब आवक की स्थिति सुधर रही है। साथ ही यार्न के भाव भी पिछले कुछ महीनों की तुलना में सुधार हुआ है। जिससे डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड की स्थिति भी बेहतर हुई है। कपास की अंतराष्ट्रीय कीमतों और देश में चल रही कपास की कीमतों के बीच का अंतर भी काफी हद तक कम हुआ है। उम्मीद है जल्द ही निर्यात की मांग भी दस्तक देगी।

एमपी से इंडस्ट्री माइग्रेशन का असर

महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में लगभग 30 लाख गांठ का कपास कारोबार होता है। 350 से ज्यादा जिनिंग फैक्ट्री यहां मौजूद है। लेकिन अब बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश से माइग्रेट होकर व्यापारी यहां जिनिंग शुरू कर रहे है। पिछले 2 सालों में यहां कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया है। नरखेड और वणी में मध्यप्रदेश के कई बड़े व्यापारी यहां अपना व्यापार फैला रहे है। ऐसे में विदर्भ को यदि प्रीमियम झोन में लाना है तो जिनर्स को डिस्पेरिटी पर काम करना बंद करना होगा।

गलत नहीं है MCX

एमसीएक्स के विषय में उन्होंने कहा कि एमसीएक्स गलत नहीं है इसे देखने का सबका नजरीया अलग-अलग है। वास्तव में यह व्यापार को आसान बनाने का एक टूल है लेकिन कुछ लोगों ने इसे सट्टा बजार के रूप में इस्तेमाल कर इसे सट्टाबाजार की संज्ञा दे दी। जबकि यदि इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बेहतरीन हेजिंग प्रोडक्ट साबित हो सकता है। व्यापारियों के साथ ही किसान भी इसके जरिये कॉटन भाव की हर हलचल से अपडेट रह सकते है। सट्टे को रोकने के लिए इस पर स्टॉक लिमिट लगाना आवश्यक था और वो संशोधन एमसीएक्स ने अपने नए प्रारूप में किया भी है।

MCX
METAL & ENERGY
Trade with Trust

इससे बुरा दौर देख चुकी है इंडस्ट्री

कपास उद्योग के लिए यह समय कठिन जरूर है लेकिन इससे भी विकट स्थिति उद्योग पहले देख चुका है। जो लोग लंबे समय से इस उद्योग में है वे जानते है कि, साल 2011-12 में जब कपास के भाव महज 15 दिन में 62,000 से 27,000 रूपए पर आ गए थे, तब सैकड़ों की संख्या में जिनिंग फैक्ट्री और स्पिनिंग मिल्स बंद हुई थी। वो दौर इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा था।

सुझाव

यह तय है कि यदि कपास की यील्ड बढ़ाई जाए तो टेक्सटाइल इंडस्टी में भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। वर्तमान में हमारे यहां कॉटन के जो सीड उपलब्ध है उनसे 34 प्रतिशत लिंट प्राप्त होती है जबकि विदेशों में जिन बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे 40 से 42 प्रतिशत लिंट मिल रही है। हमारा पूरा फोकस लिंट को बढ़ाने पर होना चाहिए।

X

ORGANIC

Crucial challenges in the way of develoment of ORGANIC food MARKET in India

SWATI AGRAWAL
(Blogger)

It's been nearly 3 years pandemic hit with its first wave all around the world. It well made understand the people that health is the real wealth and brought a drastic change in their food consumption habits. People now seem to be more inclined towards quality and organic food which is why there is a steep increase in demand of sustainably grown food products in Indian market. People globally have taken a healthier turn by including organic food items as an essential part of their regular diet.

As estimated by industry experts, the Indian organic food market is expected to reach $10 billion by the year 2025. However, there's still a long way to go. India holding 20% population of the world itself, it is only able to consume 1% organic produce of the total organic produce. Apparently, there are a lot many loopholes which yet need to be addressed to take the Indian organic market a level up.

India is blessed with the largest farmlands of the world and most of its economy is based on agriculture. As per APEDA, Madhya Pradesh has the largest acreage under organic cultivation (11.61 lakh hectares) and holds 27% of India's total acreage of organic cultivation. Some of the major organic food clusters in MP are Badwani, Jhabua, Alirajpur, Dindori, Chhindwara, Mandla, Sheopur, Guna, Mandsaur etc.

Below listed are some of the challenges that the Indian organic food industry faces :–

1. Limited Awareness – There's still a myth in the Indian society of considering organic food as a high status symbol and luxury rather than a basic necessity for good health. People know organic more as something hi-fi and unreachable rather than a sustainable solution.

2. Opting for a low-priced product – Indian people have huge variances with respect to their disposable incomes. Even if, there's a slight difference in the product price, it can make them opt for a cheaper product rather than a high-quality, fairly priced product which can benefit their health effectively.

3. Non-supportive retail market – Retailers mostly choose a fast-moving cheaper product to sell rather than risking the shelves with a lesser-known organic product. The label "organic" puts the shopkeepers in an anxious state of thinking about the returns, profit and investments. This creates a huge gap between the manufacturers and buyers which make the products even more unreachable for the latter.

4. Traditional farming habits – Indian farmers have become so familiar with the traditional farming practices of using chemical fertilizers that they are least bothered to learn the new methodologies of sustainable farming. Most of the farmers do not get instigated of adopting organic farming techniques fearing of not getting the results as the fertilizer-based farming gives.

5. Administrative support - Currently, government bodies are providing subsidies for chemical fertilizer which attract farmers more towards them. Better understanding of organic farming and knowledge of its insights is very crucial for the farmers to motivate them for this transition. Also, recovery and insurance policies in case of crop losses in organic farming can boost up the will to shift to organic cultivation.

6. Understanding the demand and supply gaps – It is observed in some instances that the demand of some comparatively popular organic item is more than its supply. Whereas it also happens that a particular item is supplied more than its demand. This supply chain needs to be balanced in either ways.

There is still so much to be looked upon in the organic food market. Organic should be given the status of an industry and specific policies should be implemented to take it to a level higher. However, it cannot be denied that organic products have gained the spotlight and popularity among the mass in recent years. Despite of the odds, the sector seems to move ahead gradually and consistently.

CFTS

Cotton Fiber Testing Services

Delivering Accurate & Reliable Results

"FIRST"

Uster HVI 1000 Cotton Testing Laboratory in
Telangana & Andhra Pradesh

- Convenient location - 5 min walking distance from MGBS Bus Stand, Hyd
- Switzerland technology - Uster HVI 1000
- Testing according to global standards
- 12 hours of conditioning as per ICA Bremen Rules (Germany)
- Reports delivered through email and whatsapp

WANT ACCURATE AND DEPENDABLE RESULTS ?

Pickup services from MGBS Bus Stand, JBS Bus Stand and from private bus points

Cotton Fiber Testing Services (CFTS)
Flat No. 15-4-67, 4th Floor, Saraswati Complex, Old Bus Stand Road, Gowliguda Chaman, Hyderabad - 500012.

Phone Number: 91211 82226, 91210 49801 | Email ID: cfts.hyd@gmail.com

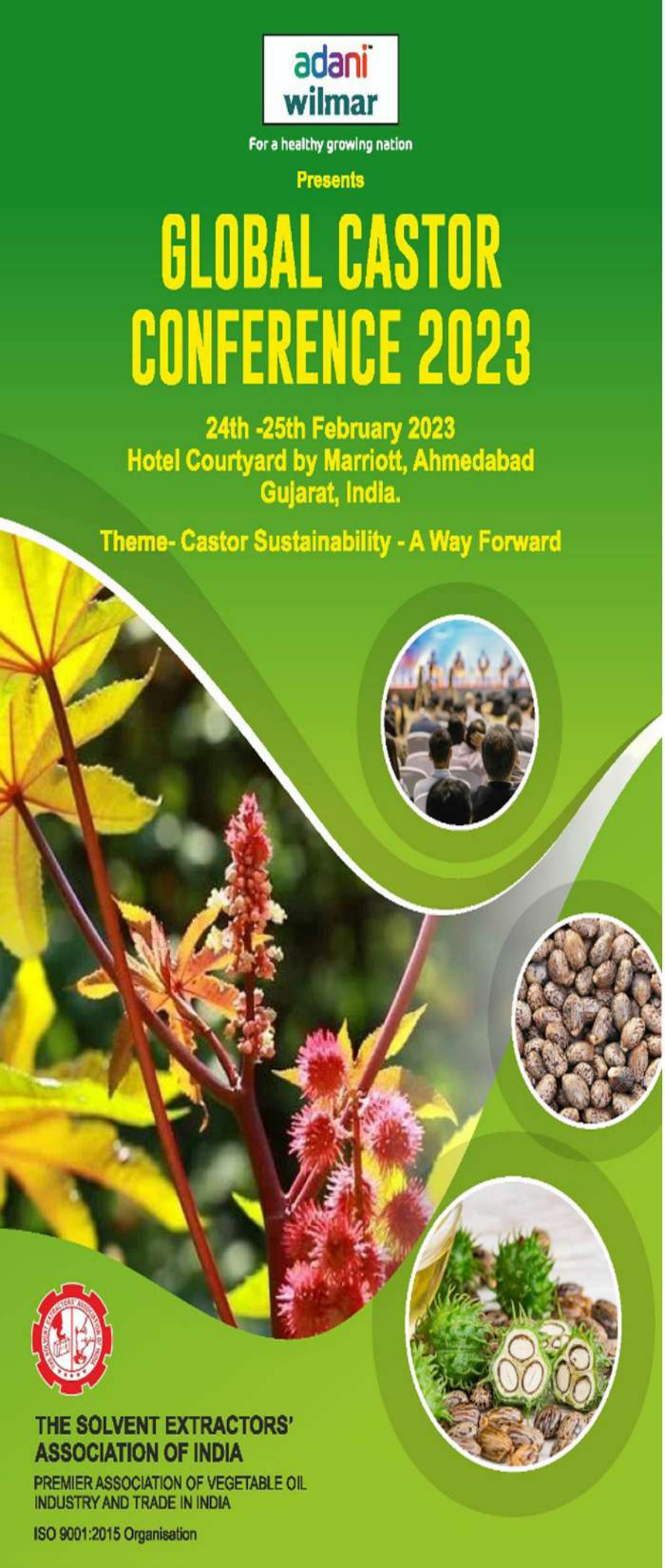

UPCOMING TRADE FAIR

National

TECHNOTEX INDIA 2023

ADD - Bombay Exhibition Centre (BEC), Mumbai, India.
DATE - 22nd Feb, 2023 to 24th Feb, 2023
(Technical Textiles)

ITMACH India 2023

ADD - Helipad Exhibition Centre Swarnim Park, Near Jilla Panchayat, Sector 17, Gandhinagar, Gujarat - 382016
DATE - 1st Mar, 2023 to 4th Mar, 2023
(Textile Machinery & Accessories)

National Conference TEXCON 2023

ADD - Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, India, Indore, India
DATE - 3rd Mar, 2023 to 4th Mar, 2023
(Textile)

International

Spinexpo Shanghai 2023

ADD - Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, Shanghai, China
DATE - 28th Feb, 2023 to 2nd Mar, 2023
(yarns, fibres)

Bishkek Fashion & Textile Exhibition 2023

ADD - Bishkek, Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan.
DATE - 2nd Mar, 2023 to 4th Mar, 2023.
(Yarn, Technical textiles)

NEWS HIGHLIGHTS

(JANUARY 2023)

नए साल की शुरूआत में ही शेयर मार्केट हुआ धराशाही, 2 जनवरी को सेंसेक्स 61167 के स्तर पर था जबकि माह अंत में 1618 अंक घटकर पहुंचा 59549 के स्तर पर ।

डॉलर के मुकाबले रूपये ने इस महीने हासिल की थोड़ी मजबूती, 82 पैसे मजबूत होकर माह अंत में कीमत रही 81.92 रूपए।

कपास उद्योग के पीक सीजन में गुजरात में जिनिंग फैक्ट्रीज का हुआ बुरा हाल, 60 प्रतिशत से ज्यादा फैक्ट्री हुई बंद।

अमेरिका में प्रतिबंधित है झिंजियांग कॉटन लेकिन ब्रांडेड गारमेंट अब भी कर रहे इसका इस्तेमाल।

महाराष्ट्र के किसानों ने कपास बेचना किया बंद,प्रदेश की 80 फीसदी जिनिंग फैक्ट्री हुई बंद।

कमजोर मांग से परेशान होकर दक्षिण के कपड़ा उद्योग ने की ऋण और निर्यात सहायता की मांग।

पाकिस्तान की स्पिनिंग मिल्स ने विलंब शुल्क और कंटेनर निरोध शुल्क में छूट देने की मांग की।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन का असर- 2050 तक पंजाब में कपास, मक्का की उपज 11 से 13 प्रतिशत तक घट जाएंगी।

कपास कीमत और माल भाड़े में कमी से कपड़ा व्यापारियों को स्थिरता की उम्मीद।

कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपास की गांठों के लिए लॉन्च किया जाएगा नया क्वालिटी कंटोल ऑर्डर।

वीएसएफ निर्माताओं को क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलने का बड़ा समय, कपड़ा उद्योग ने फैसले का किया स्वागत।

निजी व्यापारियों द्वारा कम कीमत मिलने से निराश है आदिलाबाद के किसान, मजबूरन महाराष्ट्र जाकर बेच रहे अपना माल।

Arrival Report

धीरे-धीरे सुधर रही है कपास आवक

COTTON ARRIVAL MONTH WISE

SMART INFO SERVICES
CALL : 91119 77771 - 5
Email : india.smartinfo@gmail.com

STATE	2022-2023					
	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUARY	TOTAL
Punjab	11,363	21,884	36,277	34,900	22,700	127,124
Haryana	109,096	131,931	145,783	131,500	65,000	583,310
Upper Rajasthan	50,410	267,138	314,082	228,500	189,500	1,049,630
Lower Rajasthan	41,460	238,787	216,483	105,100	76,000	677,830
Total North Zone	**212,329**	**659,740**	**712,625**	**500,000**	**353,200**	**2,437,894**
SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77771 - 5						
Gujarat	44,250	290,000	966,000	1,001,000	1,125,000	3,426,250
Maharashtra	12,600	86,400	353,000	485,000	717,000	1,654,000
Madhya Pradesh	25,800	70,000	244,000	213,000	299,500	852,300
Total Central Zone	**82,650**	**446,400**	**1,563,000**	**1,699,000**	**2,141,500**	**5,932,550**
Telangana	2,100	38,400	202,000	248,000	292,000	782,500
Andhra Pradesh	48,600	78,300	150,500	188,000	203,000	668,400
Karnataka	42,400	82,500	259,000	208,500	145,000	737,400
Tamil Nadu	40,200	30,500	29,200	20,800	20,000	140,700
Total South Zone	**133,300**	**229,700**	**640,700**	**665,300**	**660,000**	**2,329,000**
Orissa	-	-	13,000	42,500	67,000	122,500
Others	-	-	5,000	10,000	15,000	30,000
TOTAL ARRIVAL	**428,279**	**1,335,840**	**2,934,325**	**2,916,800**	**3,236,700**	**10,851,944**
NOTE : ARRIVAL FIGURES ARE TENTATIVE MAY BE POSIBLE 5/10 % PLUS MINUS						

कपास सीजन 2022-23 में कपास उद्योग के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी कपास की धीमी आवक। अच्छी पैदावार के बावजूद इस बार मंडियों में आवक की गति बहुत धीमी रही। जिसके चलते जिनर्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन, अच्छी खबर यह है कि जनवरी से आवक की स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। व्यापार के जानकारों की माने तो कपास की कीमतों में स्थिरता आने से यह बदलाव हुआ है। किसान अब ज्यादा कीमत मिलने का और इंतजार नहीं कर रहे है। और मौजूदा भाव में अपना माल बेचने को तैयार है।

पिछले 5 महीनों की आवक की रिपोर्ट पर नजर करें तो नार्थ झोन को छोड़ अन्य दोनों झोन सेंटल और साउथ में आवक का ग्राफ बढ़ोतरी की दिशा में है। नार्थ झोन में बारिश से फसल को नुकसान होने की वजह से पैदावार ही कम हुई है और चूंकि वहां सीजन भी जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए स्थिति विपरीत है। अन्यथा जनवरी का महीना कॉटन आवक के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है।

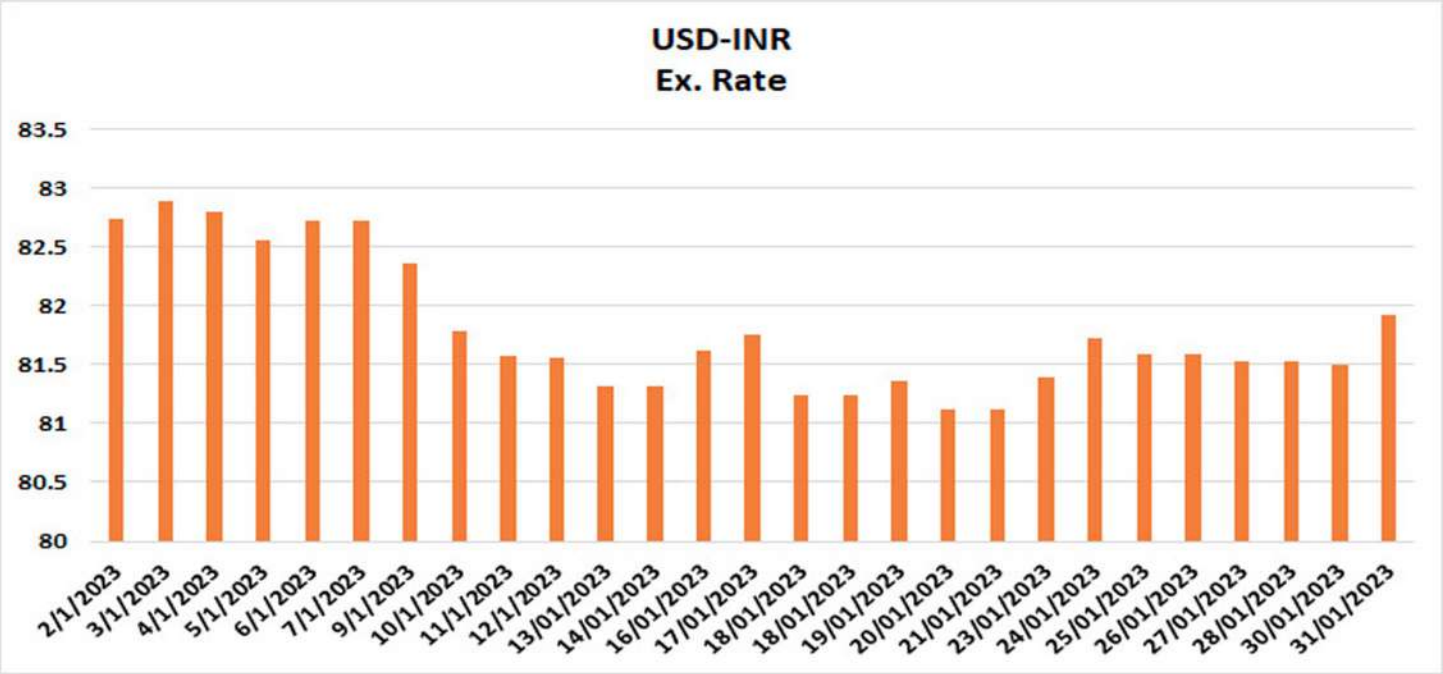

जनवरी माह में डॉलर के खिलाफ रूपए की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। हालांकि **81** से **83** रूपए के बीच ही घूमती रही। माह की शुरूआत में **2** जनवरी को डॉलर की कीमत **82.50** रूपए के स्तर से ज्यादा थी जबकि सप्ताह अंत में **31** जनवरी को यह घटकर **82** रूपए से भी कम रह गई। पहले सप्ताह में डॉलर की कीमतें अपने उच्च स्तर के आस-पास ही रही। जबकि दूसरे सप्ताह से इसके कीमत में गिरावट देखने को मिली। पूरे महीने में सबसे कम कीमत **20** और **21** जनवरी को रही।

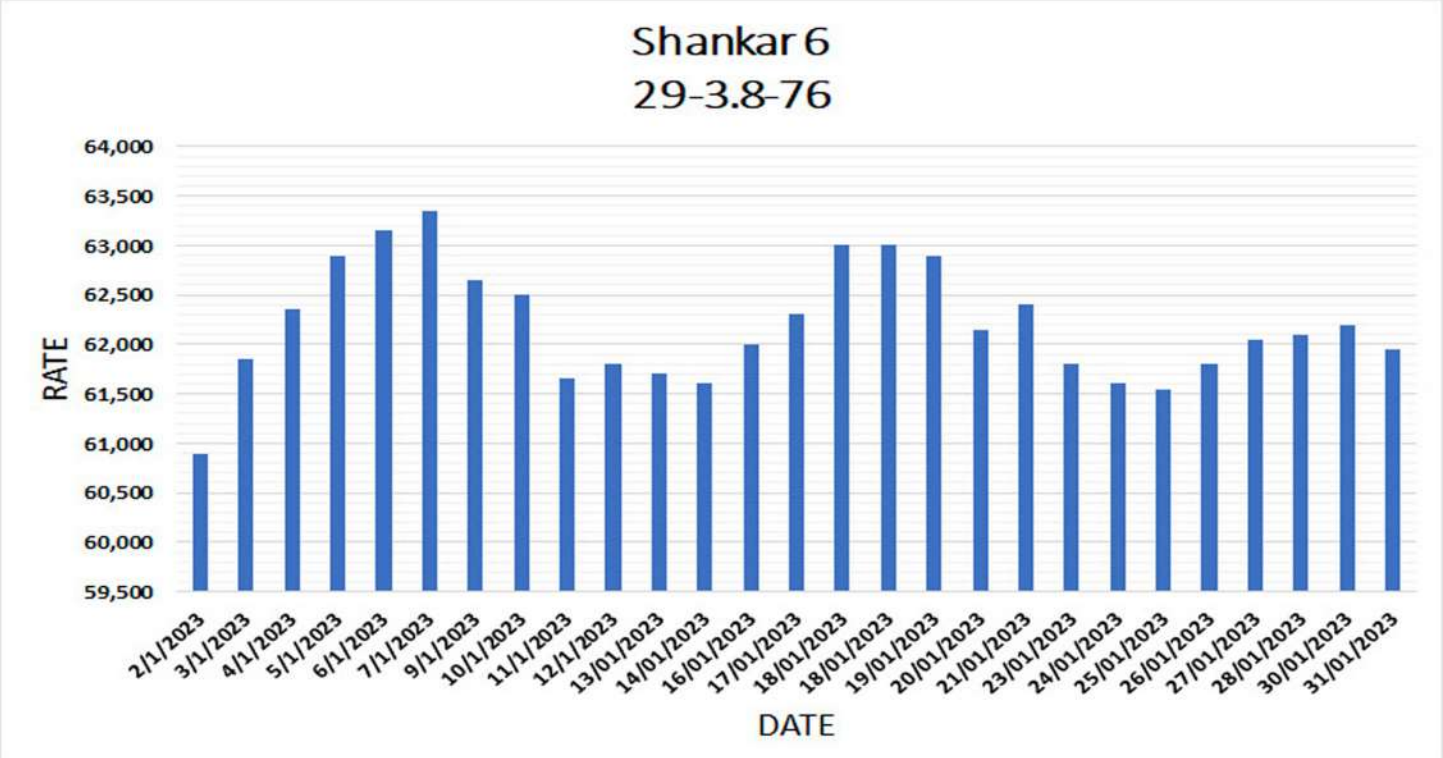

कॉटन फिजिकल मार्केट में भाव गिरने का सिलसिला तो जनवरी माह के पहले से ही शुरू हो चुका था जो अभी भी बरकरार है। गुजरात के शंकर-**6** के एक महीने के भाव पर गौर करें तो इसके भाव **61** हजार से उपर और **63500** से कम ही रहें। पूरे महीने में शंकर-**6** के सबसे ज्यादा भाव **7** जनवरी को देखे गए जबकि सबसे कम कीमत माह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार **2** जनवरी को ही रही। शंकर-**6** के पूरे महीने के उतार-चढ़ावप र आधारित एसआईएस की स्पेशल रिपोर्ट ।

MEET OUR TEAM

RAKSHA BHAGAT JAIN

[MANAGING EDITOR AND MEDIA HEAD]

Raksha Bhagat Jain posseses more than 10 years of experience in Journalism. As a journalist, she has led diversified projects for companies in terms of interviews and articles of the renowned dignitaries of the fraternity and provide fair and unbiased news and information on varied platforms.

THE EDITOR OF COT COSMOS

SHLESHA LAHOTI

[GRAPHIC DESIGNER & CREATIVE HEAD]

Shlesha Lahoti, Graphic Designer by proffesion, serves as a Creative Head of the company. She has been delivering all the creative assignments that has been doing commendable work in terms of creativity and innovation.

THE DESIGNER OF COT COSMOS

ROHIT DHAKORIA

[BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE / COTTON ANALYST]

Rohit Dhakoriya is one of the employees who have been building blocks of the company. He has become an expert in even the minute specifics of cotton over the years. He strives to deliver quality insights of the cotton market both timely and precisely.

THE DATA ANALYST OF COT COSMOS

SIS CONNECT

For daily Market updates and all your textiles related issues **DOWNLOAD** our app now!!

INSTALL NOW

(Register now for free trial)

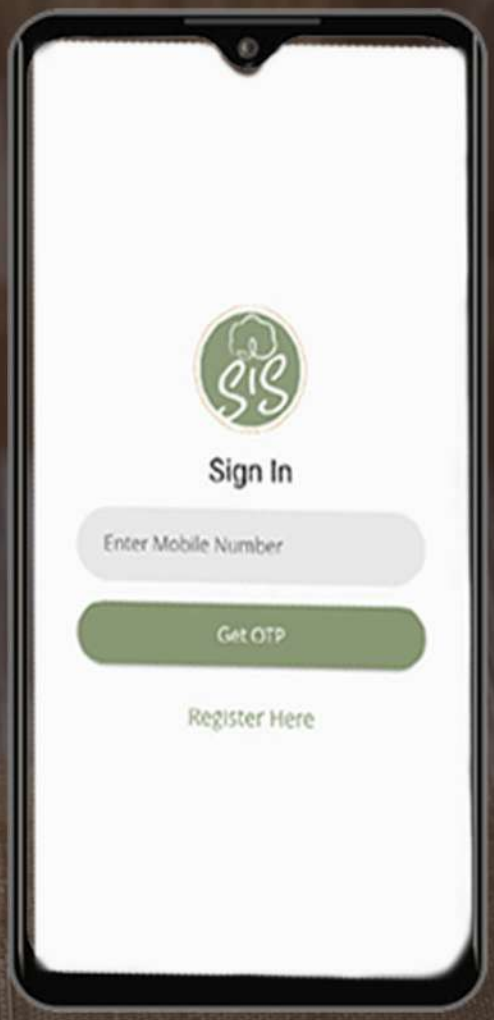

RAKSHA BHAGAT JAIN (EDITOR) / CONTACT - +91 - 74150 28064